ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE

24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of the Press briefing Held at 1615 Hours 25.08.2014

Dr. Shakeel Ahmad addressed the media today.

डा. शकील अहमद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कल सतना में मध्य प्रदेश में एक बहुत ही दु:खद घटना हुई। एक मंदिर में भगदड़ में लगभग दस लोगों की मृत्यु हुई और लगभग साठ के आसपास लोग घायल हुए। हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से इस पर दु:ख प्रकट करते हैं। जो लोग दिवंगत हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दु:ख को सहने की शकित दे। जो घायल हैं हम उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, उनके जल्द ही सेहतमंद होने की दुआ करते हैं।

डा. शकील ने कहा कि यह पहली दुर्घटना नहीं है। इसके पहले मध्य प्रदेश में, मुझको याद पड़ता है, दो बड़ी दुर्घटनाएं मंदिरों के प्रांगण में ही कुव्यवस्था के कारण मध्य प्रदेश सरकार के रहते इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुर्नावृत्ति ना हो, उसका यथासम्भव प्रयास करना चाहिए। इस तरह के मामलों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल खुले मन से मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहण करें।

डा. शकील ने कहा कि आज देश के कुछ उपचुनाव के नतीजे आएं हैं। संसद और विधानसभाओं के चुनाव में वोटिंग का नमूना अलग–अलग होता है। मगर पिछले लोकसभा के चुनाव के बाद से भाजपा के द्वारा एक मोदी फैक्टर का नाम लेके कि मोदी जी के नाम की हवा चल रही है पूरे देश में और पूरा देश मोदीमय हो गया है और सारे वोट मोदी जी के नाम पर ही पड़ने वाले हैं चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या जहां जिला परिषद में या और चीजों में पार्टी के आधार पर चुनाव होता है, यह हवा बनाने का प्रयास भाजपा की ओर से किया जा रहा था। पिछले भी कुछ नतीजों ने जैसे उत्तराखण्ड विधानसभा की तीन सीटों का चुनाव हुआ, लोकसभा की उत्ताखण्ड की हम पांचों सीट हार गए थे, लेकिन तीन की तीन उपचुनाव वाली सीटें हम जीते। उसके बाद जिलापरिषद के चेयरमैन का चुनाव हुआ। 11 जिलों में से 9 जिले कांग्रेस पार्टी ने जीते और वो बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी कि सीधे जनता वोट देती है और 11 में से 9 सीटें मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखण्ड में जीती,

तो यकीनी रूप से जो एक मोदी जी के नाम की हवा बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो कमजोर हुई है और आज के उपचुनाव के नजीतों ने एक तरफ से पूरी तरह से इस बात को नकार दिया और एक तरह से हम देखें, मैंने पहले ही कहा है कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अलग–अलग नमूने पर होता है परन्तु भाजपा की एक कोशिश थी कि कहीं कुछ नहीं है, कहते हैं एक मोदी नाम केवलम, उस पर जीतेंगे तो वो आज एक तरह से देश की जनता ने या जहां भी चुनाव हुआ था, और यह चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ था मध्य भारत में, उत्तर भारत में, बिहार में हुआ था या पूर्व भी कह सकते हैं उसको, दक्षिण भारत में कर्नाटक में चुनाव हुए थे तो लगभग सभी दिशाओं में या कई दिशाओं में चुनाव हुआ था देश के और जो इसके नतीजे हैं वो क्षेत्र पोजिटिव हैं एन्टी भाजपा पार्टियों के लिए।

एक तीसरे मुद्दे पर भी हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पिछले काफी दिनों से जो पाकिस्तान युद्ध–विराम का उल्लंघन कर रहा है और सिर्फ हवा में गोली नहीं चला रहा है, यह मेरी सेनाओं पर चला रहा है, उन पर तो चला ही रहा है, साथ–साथ जो नागरिक हैं, वो भी इसमें प्रभावित हो रहे हैं। एक पिता–पुत्र की मृत्यु हुई, कई लोग घायल हुए। लगातार आप टीवी चैनल के लोग व प्रिन्ट मीडिया के लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं, छाप रहे हैं कि लोग अपना–अपना घर छोड़ कर भागने पर मजबूर हैं। इस तरह की छुट–पुट घटनाएं मुझको याद नहीं है कि इतनी गंभीर यपूीए के शासनकाल में हुई हों। लेकिन पिछले दो–चार दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, जो इनका आकार–प्रकार है वो मुझको याद नहीं है कि यूपीए के शासनकाल में कभी इस तरह हुआ हो। और इतनी गंभीर बातों के बाद भी भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी जी चुप हैं कहते हैं कि हमारी सेनाएं सक्षम हैं उनका जवाब देने के लिए तो युपीए सरकार में सेनाएं सक्षम नहीं थी क्या? और उस समय नरेंद्र मोदी जी कहते थे पन्द्रह अगस्त के प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर उन्होंने कहा spineless प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कुछ खरी–खोटी बात और साफ–साफ नहीं बताई। ना केवल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री खामौश रहे, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने बल्कि आज भी वे खामौश बैठे हैं। अमित शाह जी गए थे काश्मीर में उन्होंने कहा कि सेनाएं कार्रवाई के लिए सक्षम हैं, उस समय भी सक्षम थीं। नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि कमजोरी सीमा पर नहीं है, कमजोरी दिल्ली में बैठे हुए लोगों के दिमाग में है। हम लोग तो उनकी बात को सही नहीं मानते हैं अगर उनकी ही बात को सही माना जाए तो यह बीमारी उनके दिमाग में कुछ ज्यादा लग गई है, लगता है, दिल्ली आने के बाद। इसलिए यह गंभीर विषय है और इनकी तरफ सरकारों को ध्यान देना चाहिए– चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार सतना के मामले को लेकर हो या फिर हमारी सीमाओं पर विशेषकर चीनी घुसपैठ और पाकिस्तान का युद्ध विराम उल्लंघन, इन पर निश्चित रूप से सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे लगे कि हम बिल्कुल असहाय नहीं है, भारत भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, एक बात और भी आती है कि स्वभाविक रूप से हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे इस तरह की बातें बन्द हों, हम बात करें, हम संवाद भेजें, हमको जो भी करना है, देश की हैसियत से हम करें जिससे इस तरह की घटनाएं रूक सकें।

एक प्रश्न पर कि बिहार की तर्ज पर, क्या पूरे देश में गठबंधन की तैयारी करेगी कांग्रेस पार्टी, डा. अहमद ने कहा कि हर राज्य की अलग–अलग परिस्थिती है हो सकता है कि कहीं गठबंधन से फायदा हो। कभी–कभी गठबंधन होने से घाटा भी हो जाता है तो राज्यों को ध्यान में रखकर राजनीतिक पार्टियों को फायदा लेना चाहिए। जहां तक बिहार का प्रश्न है, मेरा अपना मानना है कि यह गठबंधन अगर थोड़ा पहले हुआ होता तो शायद परिणाम हम लोगों के पक्ष में कुछ और अच्छे होते, गठबंधन थोड़ा देर से हुआ, आखिरी समय हुआ। मानव संबंध कोई बिजली का बटन नहीं है कि आन कर दिया और पार्टी केडर को हम कह दें कि साथ आ जाओ तो, साथ आ गए, अलग हो जाओ तो अलग हो गए। राजनीतिक पार्टियों के केडर जमीन पर काम करते हैं एक दूसरे के साथ बैठते हैं। 15, 20 साल से हम अलग–अलग दिशाओं में काम कर रहे थे, जो बात हुई, अगर वो थोड़ी और पहले होती तो और सम्बद्धता पैदा होती और भाजपा के जो feel good factor था वो और बुरी तरह नष्ट होता जो अभी हुआ है।

एकला चलो वाली नीती रही है कांग्रेस की विगत में और अब जो मौजूदा हालात हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी गठबंधन की तरफ अग्रसर होगी राष्ट्रीय स्तर पर, डा. अहमद ने कहा कि कांग्रेस ने जहां आवश्यक समझा है वहां एकला चलो की भी राजनीति अपनाई है और जहां आवश्यकता हुई वहां गठबंधन भी किया है यही लोकसभा में हुआ है, यही विधानसभाओं में भी हुआ है। हम अभी कर्नाटक में अकेले लड़े हैं और मध्य प्रदेश में भी हम अकेले लड़ें हैं और बिहार में हमने गठबंधन से लड़ाई जीती है। हर राज्य की अलग–अलग परिस्थितियां होती हैं।

कोल ब्लाक आवंटन पर उच्चतम न्यायालय के निर्देष के बाद कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया पूछे जाने पर डा. शकील अहमद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला अभी आया भी नहीं है और मैंने देखा भी नहीं है, उसको देखने के बाद कुछ बात की जा सकती है। स्थायी कमेटी की भी एक रिपोर्ट आई थी इस विषय में, जिसमें कहा गया था कि 1993 के बाद से 2009 तक जो कोल ब्लाक का आवंटन हुआ है, वो उतना पारदर्शी नहीं है जितना होना चाहिए। यह बात सही है कि हमारी अर्थव्यवस्था 1991 में खुली, डा. मनमोहन सिंह जी वित्तमंत्री थे, उनके समय में और 1993 से कैपिटल कोल ब्लाक के आवंटन की लोगों को जानकारी होने लगी। उसी 1993 से 2009 के बीच में एक पीरियड है छः सालों का, 1998 से लेकर 2004 तक का जो भाजपा के शासनकाल का है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में सरकार बनी थी, और वो उस सरकार के प्रधानमंत्री थे, और उनके शासनकाल में जो आवंटन हुआ है और हम पर आरोप कौन लगा रहा था भाजपा के लोग, तो हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा कि ये नीति एवं पद्धति उन्हीं के समय से चल रही थी, बल्कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार को कि 1998 से 2004 तक तो कोल ब्लाक का आवंटन हुआ उसमें विज्ञापन नहीं जारी किया गया, जहां तक हमारी जानकारी है। डा. मनमोहन सिंह की सरकार आने के बाद विज्ञापन की बात की। वहां स्क्रीनिंग कमेटी हुआ करती थी जिसमें राज्य के मुख्यमंत्रियों के प्रतिनिधि के रूप में मुख्य सचिव बैठा करते थे और

यह तो रिकार्ड में मौजूद है कि उन्होंने कंपनियों के नाम लेकर पूरे सुझाव दिए हैं यह मैं यूपीए शासनकाल का बता रहा हूं। तो स्वभाविक रूप से इन सब पर जब उच्चतम न्यायालय विस्तृत फैसला करेगा और जब उनका निर्णय आएगा, तब हम लोग कुछ बात करने की स्थिती में होगें। परन्तु उच्चतम न्यायालय के इस फैसले ने यह बात जरूर साबित कर दी कि वो भाजपा या एनडीए जो आरोप लगा रहा था यूपीए पर, वो बिल्कुल गलत था। कोल ब्लाक का आवंटन उनके समय में भी बहुत गलत तरीके से हुआ था।

एक अन्य प्रश्न पर कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमित शाह कथुआ में रैली किए हैं, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा वहां सरकार बनाने में कामयाब होगी, डा. अहमद ने कहा कि प्रयास तो वो बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन सफलता उनको नहीं मिल रही थी। संसद में एक सफलता मिली जिस कारण से उनको फील गुड हुआ था और प्रधानमंत्री जी वहां–वहां घूम रहे थे जहां–जहां चुनाव होने वाले हैं वो जम्मू–कश्मीर गए, वहां उन्होंने कुछ कोशिश ऐसी की जो अच्छा नहीं लगता है किसी भी मुख्यमंत्री के साथ या प्रधानमंत्री को। फिर वो गए महाराष्ट्र शोलापुर में जो वहां बात हुई, वहां के मुख्यमंत्री के साथ, फिर वो गए हरियाणा वहां पर जो उनका आचरण रहा वहां के मुख्यमंत्री के प्रति और फिर वो गए झारखण्ड। वहां जो आचरण रहा प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी का मुझको लगता है इस रिजल्ट में वो बातें भी कहीं ना कहीं मतदाताओं के दिमाग में हैं कि जो एक संवैधानिक पद है जो एक बड़ा मर्यादित पद है प्रधानमंत्री का उस पर बैठने वाले व्यक्ति का, इस तरह का और उनकी पार्टी का इस तरह का आचरण हो मुझको लगता है कि एक चीज पर वोट का फैसला नहीं करता है, यह बात भी कहीं ना कहीं आचरण जो समझता हूं कि यह उनके खिलाफ जा रहा है।

श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं श्री राहुल गांधी जी के गठबंधन के विचारों पर पूछे गए प्रश्न पर डा. शकील अहमद ने कहा कि 2014 में बिहार में जो चुनाव हुआ था उसमें हम लालू यादव जी की पार्टी के साथ लड़े, और उसमें पूरी सहमति थी, श्री राहुल गांधी जी की, तो हमने लालू यादव जी को हाशिये पर नहीं भेजा था। चूंकि अदालत का एक आर्डर था इसलिए वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे लेकिन उनके साथ हमारा गठबंधन हुआ था, उनके साथ समझौता हुआ था इसलिए आपका जो प्रश्न है मैं समझता हूं कि उसका उत्तर इसी से मिल जाएगा कि हम लोगों ने लालू यादव जी को साईड लाईन नहीं किया था और श्री राहुल गांधी जी गठबंधन के पक्ष में थे और तब गठबंधन हुआ था। अगर श्री राहुल गांधी जी विरोध कर देते तो शायद गठबंधन नहीं होता।

To another question on the reaction of the Congress party that the Governor of Maharashtra has resigned today and it may be possible that Smt. Sheila Dikshit may also resign today since all the Governors are sent to Mizoram which has been turned as dumping ground, Dr. Ahmad said this is between the government, the President and his representatives in States, the Governors of the

respective states but, of course, it looks odd when you are treating people sitting on the constitutional posts in this fashion or in this manner and of course, there are speculation or apprehension that most of the appointees of UPA government on the post of Governors - this present government will try to humiliate them, will try to remove them from that constitutional post in spite of the judgment of the Supreme Court in a previous matter – Governor from Uttarakahand Mr. Qureshi has gone to the Supreme Court, so we should wait for the judgment or for the direction of the Supreme Court but insulting the people sitting on the constitutional posts does not speak well of a government.

राज्यपालों के तबादले के बारे में, डा. अहमद ने पुनः कहा कि श्रीमती कमला बेनीवाल जी तो मिजोरम गईं थीं जब उनको गुजरात से भेजा गया था। बेनीवाल जी वहां रहीं, उसके बाद उनके साथ ऐसा व्यवहार इस सरकार ने किया, इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसको अपनी इज्जत प्यारी हो, तो थोड़ा डरता है कि सरकार उसके साथ क्या व्यवहार करेगी। इसलिए हो सकता है कुछ राज्यपालों ने इन्कार किया हो।

On another question whether Smt. Sheila Dikshit will play active role in the forthcoming Delhi Assembly elections, Dr. Ahmad said this is hypothetical because she is still the Governor and holding the constitutional post. When she will not be holding any constitutional post and when she will join politics actively then the party will decide on it. If she joins some other party, who knows. She is on a constitutional post; she is not a Member of the Congress party. It is for her to decide and choose any political party. How I can comment at this stage when she is holding the constitutional post, she is non party person now. It depends on her. She was one of the tallest Congress leaders but presently she is Governor, she is holding a constitutional post, she is not a Member of the Congress party.

To a question as to why the Governors who were appointed during UPA regime are reluctant to work in North East states, Dr. Ahmad said a number of Governors appointed by UPA are still working in North East but you have chosen one State as the dumping ground for the Governors or the transfer of a Governor. People consider in their opinion that posting from a smaller state to a bigger state is a promotion and from a bigger state to a smaller state is a punishment, is not choice posting or not a pleasant posting. That is why, I think, Governors are objecting and the manner and without taking them into confidence - this is one of the reasons without explaining them, without taking their consent, behaving like government servant. So this is, I think, objectionable for the Governor and that is why they are refusing to go to that particular place.

We have very high respect for the people of north East - the Seven Sisters state are one of the most favoured destination of a number of people and officials of our country.

एक अन्य प्रश्न पर कि मौजूदा सरकार यूपीए सरकार की advertising policy को रिव्यू कर रही है और कामकाज की जांच करेगी, डा. शकील अहमद ने कहा कि सरकार का हमेशा अधिकार है कि जिस बात को भी चाहे रिव्यू कर सकती है। आरटीआई हम लोग इसीलिए लाए थे आज उनको बहुत फायदा मिलेगा हमारे लाए हुए आरटीआई से। सरकार के कामों में पारदर्शिता के लिए हम आरटीआई लाए थे जिसका फायदा आज देश में लाखों लोग उठा रहे हैं, सिस्टम को स्थिर होने में और सही होने में उस आरटीआई ने मदद की है। इसलिए हर सरकार को यह अधिकार होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। इस मंशा से नहीं होना चाहिए कि किसी को प्रताड़ित करना है, किसी को निशाना बनाना है। यह अगर मंशा है तो थोड़ी आशंका होती है लोगों में क्योंकि उनकी मंशा बहुत साफ नहीं रहती है यह हम लोगों ने कई बार देखा है।

(Tom Vadakkan)
Secretary
Communication Deptt.